



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्रसाधारण

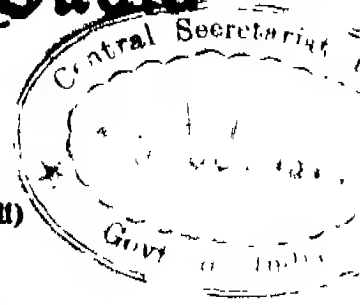
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 392] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 12, 1974/भाद्र 21, 1896

No. 392] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 12, 1974/BHADRA 21, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

ORDER

New Delhi, the 12th September 1974

S.O. 540(E)/15/IDRA/74.—Whereas by Order No. S.O. 298(E), dated the 18th May, 1974, published in the Gazette of India Extraordinary, in Part II Section 3 Sub-Section (ii) the Central Government appointed a body of persons for the purpose of making a full and complete investigation into the circumstances of the Aluminium Corporation of India Limited, Calcutta;

And whereas the said body was required to submit its report to the Central Government within a period of 15 days from the date of publication of the said Order in the Official Gazette;

And whereas the said body could not submit its report to the Central Government within the stipulated date;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 15 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby extends the date for submission of the report by the said body, upto the 15th September, 1974.

[No. F.4/6/74-CUC]
D. K. SAXENA, Jt. Secy

औद्योगिक विकास मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 12 सितम्बर, 1974

का० आ० 540 (अ)/15/अ.ई डी आर ए/74.—यतः केन्द्रीय सरकार ने, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3 उप खंड (ii) में प्रकाशित आदेश सं० का० आ० 298(ई) तारीख 18 मई, 1974 द्वारा एन्वुमिनियम कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, कलकत्ता की परिस्थितियों के बारे में समस्त और पूर्ण अन्वेषण करने के प्रयोजनार्थ व्यक्तियों का एक निकाय नियुक्त किया है ;

और यतः उक्त निकाय से, उक्त आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 15 दिन के भीतर केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट देने की अपेक्षा की गई थी ;

और यतः अनुबंधित तारीख के भीतर उक्त निकाय अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को नहीं दे सका ।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार उद्योग (विकास-और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की द्वारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, उक्त निकाय द्वारा रिपोर्ट दिये जाने के लिये उस तारीख को 15 सितम्बर, 1974 तक विस्तारित करती है ।

[सं० फा० 4/6/74-सी यू सी]

डी० के० सेक्सेना, सयुक्त सचिव ।